राज्य में टैक्सटाइल, डेटा सैन्टर व लॉजिस्टिक्स के लिये नई पॉलिसी बनी

मुख्यमंत्री भजनलाल की कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये

- टैक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के द्वारा राजस्थान को वस्त्र व परिधान का ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जायेगा।
- विश्वस्तरीय डेटा सैन्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिये निजी क्षेत्र में डेटा सैन्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान डेटा सैन्टर पॉलिसी को मंजूरी मिली।
- जीएसटी लागू होने के बाद राजस्थान कर बोर्ड का काम सीमित हो गया, अतः इसका राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया।

जयपुर, 4 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने, युवाओं को सक्षम एवं सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर्स को कुलगुरू की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ लॉज (अमेण्डमेंट) बिल लाने, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल लाने सहित, कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल एवं पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए, आज राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 कैबिनेट में मंजूर की गई।

पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजस्थान युवा नीति-2025 के जरिये, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यिमता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यह नीति युवा नीति- 2013 का स्थान लेगी।

पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद, राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था। इसे देखते हुए, राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है।

पटेल ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी प्रदान किये जाने की घोषणा की गई थी। इस बजट घोषणा की अनुपालना में कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रतिकुलपति पदनाम को भी प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू-रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 लाया जाएगा। इसके प्रारूप का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

कन्हैया लाल ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ एवं जीव विज्ञानी के पदों पर भर्ती अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अनुरूप ही, संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में भी समान पदों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की शैक्षिणक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन हेतु 5 प्रतिशत अंकों की छूट का प्रावधान किया गया है।

'अवैध विदेशी अप्रवासियों को निर्वासित क्यों नहीं किया अभी तक?'

- सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकारते हुए कहा, किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं।

नयी दिल्ली, 04 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने अवैध अप्रवासी घोषित किए गए विदेशी नागरिकों को तुरंत निर्वासित नहीं करने पर मंगलवार को असम सरकार को फटकार लगाई और उसे निर्देश दिया कि वह हिरासत में लिए गए 63 लोगों को उनके मूल देश में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेन्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राजूबाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा, आप उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते। एक बार जब वे विदेशी घोषित हो जाते हैं, तो उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं। फिर आप उनका पता मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? यह दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। पीठ ने हिरासत में लिए गए उन लोगों को निर्वासित करने के मुद्दे पर असम सरकार से पूछा, क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?

शीर्ष अदालत ने कहा कि पते के बिना भी राज्य उन्हें निर्वासित कर सकता है। उन लोगों को देश की राजधानी में निर्वासित किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा, मान लीजिए कि वह व्यक्ति पाकिस्तान से है और आप पाकिस्तान की राजधानी जानते हैं? तो आप उसे पाकिस्तान की राजधानी में भेज देते हैं।

भूटान नरेश ने महाकुम्भ में स्नान किया

- भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को महाकुम्भ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में स्नान किया।

महाकुंभनगर, 04 फरवरी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई।

भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। नामग्याल वांगचुक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संगम स्नान किया। महाकुम्भ का वैभव देखकर भूटान नरेश अभिभूत नज़र आये।

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मंगलवार को महाकुम्भ में संगम स्नान व तर्पण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

पुरोहितों ने मुख्यमंत्री और भूटान नरेश का विधिविधान से पूजन संपन्न कराया।

मुख्यमंत्री और भूटान नरेश में गंगा मां को दुग्ध और माला अर्पित किया। दोनों महानुभावों ने मां गंगा की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से भूटान नरेश को छोटा चांदी का कलश सौंपा।

संगम में स्नान-ध्यान के उपरांत भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षयवट का दर्शन करने गये। इसके बाद दोनों नेताओं ने बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए।

इसके बाद दोनों नेताओं ने बड़े हनुमान मंदिर के नजदीक बने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र पहुंचकर महाकुम्भ के दिव्य-भव्य और डिजिटल स्वरूप का भी अवलोकन किया।

महाकुम्भ नगर में भूटान नरेश की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और विष्णुस्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के महंत जगद्गुरू संतोष दास (सतुआ बाबा) सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

गोगामेडी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रोहित गोदारा, वीरेन्द्र चारण, महेन्द्र मेघवाल और गोल्डी बराड सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं।

एनआईए ने जून, 2024 में आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।

आखिर राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हूट किया गया। आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियों के कारण गरीब तबका पिछले दस साल से उसके साथ है, लेकिन देखना यह है कि इनमें से कितने आप के साथ बने रहते हैं और कितने लोग कांग्रेस के पाले में चले जाते हैं। आठ फरवरी को घोषित चुनाव परिणाम ही जन मानस की असली स्थिति को उजागर कर पायेंगे, क्योंकि खास तौर से इस चुनाव के नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल ही है।

205 अवैध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसने बताया कि अमेरिकी सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया है, जो कम से कम 24 घंटे के बाद पहुंचेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने पिछले महीने वाशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान "अनियमित प्रवास" पर चिंता व्यक्त की थी। इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजना शुरू कर दिया है और प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग कर रहा है। साथ ही प्रवासियों को रखने के लिए सैन्य अड्डे खोल रहा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 या 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करने और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के कार्यक्रम के बीच अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेजने की बात सामने आयी है।

जल जीवन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तय कर चुकी है कि ऐसे मामलों में यदि अदालत जमानत देती है तो उसे यह बताना होगा कि संबंधित आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, जबकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ईडी कोर्ट प्रसंज्ञान ले चुका है। इसके अलावा, कोई भी आरोपी यह नहीं कह सकता कि उसके सह आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसे जमानत दी जाए। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

ट्रम्प केवल बड़बोले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जा सके और एक संपूर्ण ट्रेड वॉर से बचा जा सके।

चीन पहले ही यह वादा कर चुका है कि वह फैंटानैल उत्पादन के लिए आवश्यक "प्रीकर्सर" सामग्री के उत्पादन और निर्यात को नियंत्रित करेगा। डॉनल्ड ट्रंप की मुख्य शिकायतों में से एक यह है कि चीन भारी मात्रा में फैंटनैल और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियां भेज रहा है।

वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यापार पर डॉनल्ड ट्रंप के साथ सौदा करने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं हैं। जिनपिंग भी अपने देश के दृढ़ विरोध की छवि पेश करने में रुचि रखते हैं। शी ने आयात प्रतिबंध और ट्रेड पर अन्य प्रतिबंध लागू किए हैं।

चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को टंग्स्टन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामग्री है। इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में होता है। इससे कई अमेरिकी उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं। चीन के पास ऐसी महत्वपूर्ण सामग्रियों का एक मजबूत भंडार है, जो कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पाई जाती हैं।

चीन ने अन्य कई अमेरिकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के कुछ फैशन हाउसों पर चीन के बहिष्कार आदेश लगाए गए हैं, जिससे चीन के लोगों के लिए उन उत्पादों को कहीं और से प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।

वर्तमान में टैरिफ कार्यवाही पर यह रोक एक महीने तक जारी रह सकती है, इसके बाद अमेरिका ने वादा किया है कि वह समीक्षा करेगा और नए कड़े प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन तब तक राहत है और वैश्विक बाजारों ने एक गहरी राहत की सांस ली है।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साबित होती है कि उसने बाथरूम में छिपी पीड़िता को बार-बार धमका कर बाहर बुलाने का प्रयास किया, ताकि वह पूरा अपराध कर सके। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 12 अप्रैल, 2024 को शिप्रापथ थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि वह और अभियुक्त एक घर में परिवार सहित किराए पर रहते हैं। उसकी 11 साल की बेटी 8 अप्रैल को घर में अकेली थी। इस पर अभियुक्त ने उसे रुपए देकर दुकान से सामान मंगाया। जब पीड़िता सामान लेकर उसके कमरे पर गई तो अभियुक्त ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान, पीड़िता टॉयलेट जाने का बहाना कर बाथरूम में चली गई। तब अभियुक्त उसे बाहर आने के लिए धमकाने लगा।

शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 धांधली को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमेटी द्वारा नियुक्त किए जा चुके पी.टी.आई. शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" दिए गए थे।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इन तमाम याचिकाओं के संदर्भ में जवाब दायर किया है, परंतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। नियुक्ति पा चुके इन 15-20 शिक्षकों की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ताा आर.एन.माथुर पैरवी के लिए पेश हुए थे। इन्होंने दलील दी कि जिन यूनिवर्सिटी से तथाकथित "फर्जी डिग्रियां" लेना बताया जा रहा है, उन सभी यूनिवर्सिटी से भी जवाब लिया जाए और उन्हें भी इस प्रकरण में पार्टी बनाया जाये। बहस के दौरान सामने आया कि आगरा में शिकोहाबाद स्थित जे.एस. यूनिवर्सिटी ने अदालत में जवाब दायर किया है, लेकिन इन 15-20 शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता को इस जवाब की कॉपी नहीं दी गई है। इस भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अधिकांश डिग्रियां ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी और उदयपुर की भूपाल नोबल यूनिवर्सिटी, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी मध्यप्रदेश से जारी हुई थीं तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों से भी जवाब अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ़ ने इस प्रकरण में अलग-अलग तारीखों पर 134 पी.टी.आई. शिक्षकों को जांच के बाद पद से हटाने के आदेश दिए थे। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन 134 शिक्षकों को पहले ही सस्पैंड कर दिया था। इनमें सबसे ज्यादा धौलपुर व बाड़मेर से सस्पैंड हुए है। इन जिलों से ग्यारह ग्यारह लोगों को निलम्बित किया गया और बांसवाड़ा से सबसे ज्यादा 19 पीटीआई ने निलम्बन के खिलाफ स्टे ले रखा है। इन मामलों पर अब सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। हालांकि 33 ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अदालत से स्टे ले रखा है। एस.ओ.जी. इस भर्ती से जुड़े 243 शिक्षक व अभ्यर्थियों को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है, अब तक 16 एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने अगली तारीख 6 फरवरी तय की है।

वातावरण में बढ़ता प्रदूषण व यमुना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया कि क्या हरियाणा सरकार उस पानी को विषैला बनाएगी, जिसे वे (मोदी) दिल्ली में पीते हैं।

डॉ. अरविन्द कुमार जो सुप्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट तथा स्वास्थ्य विशेष हैं, कहते हैं, "बच्चे साँस लेने में परेशानी, अस्थमा तथा स्टंटेड लंग डवलपमैंट से पीड़ित हो रहे हैं। बड़ी उम्र के लोगों में हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज (सीओपीडी) तथा अन्य गंभीर बीमारियाँ बढ़ रहीं हैं। लम्बे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।"

एक रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण, भारत में एक वर्ष में 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। दिल्ली, जो दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है, कातर नज़रों से देख रहा है कि प्रदूषित वायु के कारण, उसके निवासियों की लम्बे जीवन की प्रत्याशा (एक्स्पैक्टैन्सी) कम होती जा रही है। यह इतनी गंभीर चेतावनी है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वायु प्रदूषण का असर केवल स्वास्थ्य पर ही पड़ता है, इससे अर्थव्यवस्था और समाज भी प्रभावित होते हैं। खराब स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता को कम कर देता है तथा इससे कई स्तरों पर आर्थिक नुकसान होता है। अस्पताल में ईलाज का खर्च, अकाल मृत्यु, जीवन की कम होती गुणवत्ता आदि सरकार और समाज पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ का कारण बनते हैं।

दिल्ली के मतदाताओं की पिछले चन्द दशकों की प्रवृत्ति बताती है कि मतदाता प्राय: त्वरित लाभ, जैसे मुफ्त बिजली, पानी और यातायात को प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली की करीब 40 प्रतिशत जनता अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती है। पहले यह तबका कांग्रेस का वोट-बैंक था तथा पिछले 15 साल से यह आप का गढ़ बन गया है। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये, रोज कमाना-रोज खाना तथा वित्तीय स्थिरता जैसी चीजें प्रदूषित वायु और जल जैसे मुद्दों पर हावी रहती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, पर्यावरणीय संकटों के समाधान की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी चुनावी रणनीति सिद्ध होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली की शासन व्यवस्था का ढांचा बड़ा जटिल है। सत्ता तीन जगह- दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार तथा नगर निगम में बँटी हुई है। यह टुकड़ों वाली व्यवस्था वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों से निपटने के समन्वित प्रयासों में बाधक रहती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को जलवायु परिवर्तन से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से दिल्ली जैसे शहरों में "अरबन हीट आइलैंड" इफैक्ट बढ़ा है और ग्रीष्म ऋतु का तातमान 50 डिग्री सैन्टीमीटर तक पहुँच गया है।

असामान्य वैदर पैटर्न, जैसे भारी वर्षा, तेज लू तथा जलवायु संबंधी अन्य परिवर्तन पर्यावरण की स्थिति को हर क्षण बदतर बना रहे हैं। इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पैट्रोल, डीज़ल आदि के जलने से केवल ग्रीनहाउस गैसे ही नहीं निकलती, हवा को प्रदूषित करने वाले नुकसानदायक कारक भी बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रभावी साधनों और उपायों के बिना, दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति आगामी वर्षों में और ज्यादा खराब ही होनी है।

एल एण्ड टी, बी.ई.एल. व सीमैंस के शेयर के दाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और सिएमेंस इंडिया जैसे स्टॉक्स को सरकारी आदेशों और स्थानीय उत्पादन को दिए गए प्रोत्साहनों से लाभान्वित होने की उम्मीद है।

निवेशक सीमेंट और स्टील जैसे स्टॉक्स में भी सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील, इन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम बढ़ने से ज्यादा लाभ होने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली कंपनियों के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और रिन्यू पावर जैसे स्टॉक्स को सौर, पवन और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूल नीति प्रोत्साहनों से गति मिलने की उम्मीद है।

टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा, "भारत की हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन अपरिहार्य है, और बजट इस प्रक्रिया को तेज करता है, हमें विश्वास है कि हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करके इस यात्रा में अग्रणी होंगे।"

बजट का फोकस व्यवसायों के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को सुधारने और एणएसएमई को ऋण प्रदान करने पर है इससे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे स्टॉक्स को लाभ होने की उम्मीद है।

एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने कहा, "वित्तीय क्षेत्र को सरकार की डिजिटल और एमएसएमई ऋण पहलों से लाभ होगा," हम इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं और हमारा लक्ष्य अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने का है।

कर नीतियों को सरल बनाने और बॉन्ड बाजारों के लिए प्रोत्साहन से वित्तीय बाजारों को और मजबूती मिलेगी और इसे प्रमुख वित्तीय संस्थाओं और फिनटेक खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर होगा।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देने के कारण आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां को मजबूत ग्रोथ मिल सकती है। इन्फोसिस, टीसीएस, और विप्रो जैसे स्टॉक्स ए.आई. प्रेरित समाधानों, स्वचालन और डेटा एनालिटिक्स की बढ़ती मांग से लाभान्वित होने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने कहा, "डिजिटल परिवर्तन भारत की विकास गाथा का केन्द्र बिंदु है, हम अपने ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक रुप से निवेश कर रहे हैं।"

बजट में प्रौद्योगिकी में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है, जोस्टार्टअप्स और तकनीकी सक्षम उद्यमों को लाभ पहुंचाएगा, और बाजार के अवसरों को विस्तृत करेगा।

निहित आय और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे एफएणसीजी और खुदरा क्षेत्रों के स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। हिन्दुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), आईटीसी, और डाबर जैसी कंपनियां बेहतर खपत पैटर्न के साथ स्थिर लाभ देख सकती हैं।

हिन्दुस्तान यूनी लीवर के सीईओ संजीव मेहता ने कहा, "हम बजट में घोषित उपायों के बाद ग्रामीण मांग में मजबूत वृद्धि की उम्मीद करते हैं," शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।"

राजस्थान सरकार

अपील

प्रिय किसान साथियों,

हमारे देश की असली ताकत आप किसान हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही हम अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आपकी लगन एवं मेहनत कृषि व्यवस्था का आधार है और इस आधार को और भी मजबूत करने के लिए हम निरन्तर काम कर रहे हैं।

भारत सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है, जो न केवल आपको एक विशिष्ट पहचान दिलाएगी, बल्कि यह आपके जीवन को सरल बनाने के साथ और भी सुविधाएं लेकर आएगी।

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की आधार से जुड़ी फार्मर आईडी मिलेगी, जिससे आप विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से आपको कृषि में बेहतर निवेश का अवसर तथा कृषि विशेषज्ञों से समय पर मार्गदर्शन मिल सकेगा। साथ ही फसल बीमा, आपदा प्रबंधन के तहत सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लिए आपका ऑनलाइन पंजीकरण भी सहज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

इसके लिए 05 फरवरी, 2025 से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों में आप अपनी कृषि भूमि को आधार से जुड़वाकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करवाएं और डिजिटल भारत का हिस्सा बनें।

धन्यवाद।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान संवाद

कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600